



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ४(५)]

मंगळवार, फेब्रुवारी २५, २०२०/फाल्गुन ६, शके १९४१

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २५ फरवरी, २०२० ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

L. A. BILL No. V OF 2020.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS,
NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५ सन् २०२०।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर
संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं
सन् १९६५ जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक
का महा. ४०। नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और,
सन् २०२० इसलिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२०,
का महा. अध्या. क्र. ४ फरवरी, २०२० को प्रख्यापित हुआ था ;
४।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा लघु उपांतरण के साथ बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। १. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० कहलाए।

(२) ४ फरवरी, २०२० को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा २ में संशोधन। २. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, सन् १९६५ का महा. ४०। “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड (७) के, उप-खण्ड (दो) में, “के रूप में निर्वाचित हुए” शब्दों को पश्चात् “धारा ५१ के अधीन धारा ५१क-१ख के अनुसरण में परिषद का अध्यक्ष या” शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९६५ का महा. ४० में धारा ५१क-१ख का निवेशन। ३. मूल अधिनियम की धारा ५१क-१क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए धारा ५१क-१क का लागू न होना। “**५१क-१ख.** महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, सन् २०२० का महा. १ २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, परिषद के आम निर्वाचन और उप-निर्वाचनों के संबंध में, धारा ५१क-१क के उपबंध लागू होने से परिवर्तित हो जायेंगे और प्रत्येक परिषद का अध्यक्ष वह होगा जो धारा ५१ के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा ५१ के उपबंध लागू होंगे।”।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१क में संशोधन। ४. मूल अधिनियम की धारा ५१क की, उप-धारा (६क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

“(६ख) महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, सन् २०२० का महा. १ २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, परिषद के आम निर्वाचन और उप-निर्वाचन के संबंध में, उप-धारा (६क) के उपबंध लागू होने से परिवर्तित हो जायेंगे और प्रत्येक परिषद का उपाध्यक्ष वह होगा जो धारा ५१क के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा, ५१क के उपबंध लागू होंगे।”।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५२ में संशोधन। ५. मूल अधिनियम की धारा ५२, की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

“(४) महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, धारा ५१ के अधीन धारा ५१क-१ख के अनुसरण में अध्यक्ष की पदावधि उप-धारा (१) में यथा उपबंधित ऐसी होगी।”।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५५ का प्रतिस्थापन। ६. मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

“**५५.** (१) धारा ५१ के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने की माँग पर पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अनिम्न पार्षदों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसमें ऐसे अध्यक्ष के विरुद्ध कदाचार के आरोप अंतर्विष्ट होंगे और उसे कलक्टर को भेजा जायेगा :

परंतु, ऐसे अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी माँग नहीं भेजी जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन माँग की प्राप्ति पर, कलक्टर, ऐसे आरोपों की जाँच संचालित करेगा और ऐसी जाँच, माँग की प्राप्ति के दिनांक से एक महिने की अवधि के भीतर पूरी की जायेगी :

परंतु, किसी मामले में जाँच का ऐसा अवधि तीन महिने से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा और यदि जाँच प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों द्वारा विलंबित होती है तो ऐसे विस्तारित अवधि के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति कलक्टर द्वारा प्राप्त की जायेगी।

(३) कलक्टर, धारा ५५क के अधीन समुचित कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को जाँच के निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।”।

७. मूल अधिनियम की धारा ५८ की उप-धारा (१क) में, “ धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाए, ऐसे विकास कार्यों के ऐसे प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान में, “ धारा ५१ के अनुसरण में निर्वाचित अध्यक्ष या, यथास्थिति, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को, राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि समय-समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विकास कार्यों के ऐसे प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी, ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
५८ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ९३ की, उप-धारा (२), के, खण्ड (ग) के, परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
९३ में संशोधन।

“ परंतु, जैसा कि समय-समय पर, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकें ऐसी संविदा के लिए, अध्यक्ष की समिति (धारा ५१ के अनुसरण में निर्वाचित या, यथास्थिति, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित) और मुख्य अधिकारी उसकी प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर ऐसी संविदा को अनुमोदन देगी। ”।

९. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-१क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
३४१ख-१क का
निवेशन।

सन् २०२०
का महा.।

“ ३४१ख-१ख महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, नगर पंचायत के आम निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में, धारा ३४१ख-१क के उपबंध लागू होने से परिवरित हो जायेंगे और प्रत्येक नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होगा जो धारा ३४१ख-१ के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा ३४१ख-१ के उपबंध लागू होंगे । ”।

नगर पंचायत
के अध्यक्ष के
निर्वाचन के
लिए धारा
३४१ ख-१क का
लागू न होना।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-२ की, उप-धारा (६क) के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की
धारा ३४१ख-२ में
संशोधन।

सन् २०२०
का महा.।

“(६ख) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, नगर पंचायत के आम निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में, उप-धारा (६क) के उपबंध लागू होने से परिवरित हो जायेंगे और प्रत्येक नगर पंचायत का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा ३४१ख-२ के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा ३४१ख-२ के उपबंध लागू होंगे।

सन् २०२०
का महा.।

(६ग) “महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, धारा ३४१ख-२ की, उप-धारा (६ख) के अनुसरण में, निर्वाचित उपाध्यक्ष के पदावधि, धारा ३४१ख-२ की उप-धारा (६) में यथा उपबंधित ऐसा होगा।”।

११. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-४ की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की
धारा ३४१ख-४ में
संशोधन।

सन् २०२०
का महा.
.....।

“(४) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, धारा ३४१ ख-१, के अधीन धारा ३४१ ख-१ख के अनुसरण में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि इस धारा की उप-धारा (१) में यथा उपबंधित ऐसा होगा।”।

१२. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-५ के, स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६५
का महा.
४० की
धारा
३४१ख-५
का
प्रतिस्थापन।

पार्षदों द्वारा नगर
पंचायत के अध्यक्ष
को हटाना।

“३४१ख-५. (१) धारा ३४१ ख-१ के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष हटाए जाने की माँग पर पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अनिम्न द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसमें ऐसे अध्यक्ष के विरुद्ध कदाचार के आरोप अंतर्विष्ट होंगे और उसे कलक्टर के पास भेजा जाएगा :

परन्तु, ऐसे अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी कोई माँग भेजी नहीं जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन माँग की प्राप्ति पर, कलक्टर ऐसे आरोपों की जाँच संचालित करेगा और माँग की प्राप्ति के दिनांक से एक महीने की अवधि के भीतर ऐसी जाँच पूरी करेगा :

परन्तु, किसी मामले में, यदि जाँच प्रक्रिया, अपरिहार्य कारणों द्वारा विलंबित होती है तो जाँच के ऐसी अवधि तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और ऐसे विस्तारीत अवधि के लिए, कलक्टर द्वारा, राज्य सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।

(३) कलक्टर, उस के लिए यथा प्रयुक्त धारा ५५क के अधीन समुचित कार्यवाही करने के लिए सरकार को जाँच के निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।”।

कठिनाई के
निराकरण की
शक्ति।

१३. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, मूल अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से असंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०२० का
महा. अध्या. क्र.
४ का निरसन
और व्यावृत्ति।

१४. (१) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० सन् २०२० का महा. अध्या. क्र. ४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, नगर परिषद, और **नगर पंचायत** के अध्यक्ष, परिषद और **नगर पंचायत** के आम निर्वाचन में मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं।

सद्य स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् और नगर परिषद और **नगर पंचायत** का सुचारु कार्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों का यथोचित उपांतरण करना इष्टकर समझती है।

२. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश निम्न है,—

(क) यह उपबंध करना कि, नगर परिषद, और **नगर पंचायत** के अध्यक्ष, उनमें से निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

(ख) अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में पारस्परिक उत्तरदायित्व और समझदारी को बढ़ावा देना।

(ग) नगरपालिका क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों की गति को बढ़ावा देना ; और

(घ) आवश्यक पाए जानेवाले अन्य परिणामस्वरूप संशोधनों को कार्यान्वित करना।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था, कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का ४०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः यह महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० (सन् २०२० का महा. अध्या. क्र. ४), ४ फरवरी, २०२० को प्रख्यापित किया गया है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को लघु उपांतरणों के साथ राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,

दिनांकित १३ फरवरी, २०२०।

एकनाथ शिंदे,

नगर विकास मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रास्त है, अर्थात् :—

खंड ७.—इस खंड के अधीन, जिसका आशय, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा १८ की, उप-धारा (१-क) में संशोधन करना है, जिसमें, धारा ५१ के अनुसरण में निर्वाचित अध्यक्ष या, यथास्थिति, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को विकास कार्यों के ऐसे प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी देने के लिये जैसा कि समय-समय से, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खंड ८.—इस खंड के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम की धारा ९३ की उप-धारा (२) का परन्तुक निविष्ट करना है, जिसमें अध्यक्ष (धारा ५१ के अनुसरण में निर्वाचित, या, यथास्थिति, धारा ५१क-१क के अनुसरण में निर्वाचित, या, यथास्थिति, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे (निर्वाचित) और मुख्य अधिकारी से मिलकर बनी समिति द्वारा जैसा कि समय-समय से संविदा के प्रवर्ग को अनुमोदित करने के लिये आदेश द्वारा, राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

खंड १३(१).—इस खंड के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत किसी कठिनाई के निराकरण करने के लिये **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है।

(२) विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित २५ फरवरी, २०२०।

राजेन्द्र भागवत,

सचिव (कार्यभार),

महाराष्ट्र विधानसभा।